

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2004—आश्विन 16, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1325.—श्री शान्तनु, भा.प्र.से. (एम. टी. 1997) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001) स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, आई. एफ. ए. डी. बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री पी. सी. पाण्डे, भा. व. से. (1987) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आई. एफ. ए. डी. विलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।
4. श्री पी. नरसिम्हाराव, भा. व. से. (1987) वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1327.—श्री एस. के. केहरि, भा. प्र. से. (1992) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण एवं संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. श्री केहरि द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं श्री या. पी. गय नेताम, भा. प्र. से. संचालक, लोक शिक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे।
3. श्री भरत अग्रवाल, रा. प्र. से. (आर. आर.-85) संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है।
4. श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती ईशिता राय, भा. प्र. से. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव के प्रभार से मुक्त होंगी।

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1323.—श्री कमल प्रीत सिंह, भा. प्र. से. (2002) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालाद, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1326.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) को प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. श्री एम. एस. धुर्वे, भा. प्र. से. (1989), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त, भू-अभिलेख तथा रहत कार्य के पद पर पदस्थ किया जाता है।
3. श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त, भू-अभिलेख तथा रहत कार्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।
4. श्री ए. मिंज, (रा. प्र. से.), रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।
5. श्री अनिल टुटेजा, (रा. प्र. से.), उप-सचिव, मुख्य मंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकार, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है।

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 2-27/2004/1-8.—श्री टी. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अवकाशपुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 832/2004/1-8/स्था.—श्री जे. पी. वर्मा, स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28-6-2004 से 9-7-2004 तक कुल 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10 एवं 11 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. वर्मा को स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-19/2003/एक/2/1321.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 23/5/2004-EO/MM-I, दिनांक 14-9-2004 द्वारा श्री आर. डी. मोना, भा. प्र. से. (W.B. 1984) की नियुक्ति निज सचिव (Private Secretary) केन्द्रीय राज्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन (श्री नमो नारायण मोना) के पद पर की गई है, फलस्वरूप श्री मोना को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 864/2004/1-8/स्था.—श्री पी. सी. पाण्डेय, (भा. व. से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 805/2004/1-8, दिनांक 2 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश दिनांक 23-8-2004 से 28-8-2004 तक 6 दिन का श्री पाण्डेय द्वारा उपभोग नहीं करने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रहास बेहार, सचिव

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2/लीव/1324.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-8-2004 द्वारा श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. को दिनांक 23-8-2004 से 4-9-2004 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

क्रमांक 2225/1341/2004/1/2/लीव/1322.—श्री टी. एस. छतवाल, भा. प्र. से. को दिनांक 20-9-2004 से 1-10-2004 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 18, 19-9-2004 एवं 2 एवं 3-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री छतवाल आगामी आदेश तक सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री छतवाल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छतवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 2269/1386/2004/1/2/लीव/1319.—इस विभाग के आदेश दिनांक 29-7-2004 द्वारा डा. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. को दिनांक 23-7-2004 से 28-8-2004 तक (37 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 29-8-2004 से 8-10-2004 तक (41 दिवस) का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 9 एवं 10-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश काल में डा. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डा. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2/लीव/1320.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से. को दिनांक 13-9-2004 से 17-9-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-9-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 1-10/दो (तीन-जेल) 2001.—राज्य शासन एतद्वारा जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये निम्नांकित व्यक्तियों को तीन वर्ष कालावधि के लिये नीचे कालम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

| क्रमांक (1) | जेल का नाम (2) | अशासकीय संदर्शक का नाम (3) | पता (4) |
|----------------|-----------------------|--|--|
| 1. | उप जेल, महासमुन्द | 1. श्री द्वारिका चंद्राकर 2. श्रीमती ललिता अग्रवाल | मु. पो. बेमचा मु. पो. पिथौरा |
| 2. | उप जेल भमतरी | 1. श्री दयाशंकर सोनी 2. श्री शैलेन्द्र धेनु सेवक | जाधापुर बाई भमतरी मु. पो. सिहावा नगरी |
| 3. | जिला जेल, राजनांदगांव | 1. श्री रघुवीर बाधवा 2. श्री प्रकाश वैद 3. श्री महेन्द्र जैन, | स्टेशन पारा, राजनांदगांव गुड्डाख लाडन, राजनांदगांव मु. पो. लुखौली, राजनांदगांव |
| 4. | उप जेल, डोंगरगढ़ | 1. श्री बिरेन्द्र सोनी 2. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल | पुराना बस-स्टैंड, डोंगरगढ़ मु. पो. डोंगरगढ़ |
| 5. | सर्किल जेल, दुर्ग | 1. श्री अगरो सिंग यादव 2. श्री राजेश ताम्रकार 3. श्री कांशीनाथ शर्मा | धमधा नाला, दुर्ग ढीमरपारा, दुर्ग ब्राम्हण पारा, दुर्ग |
| 6. | उप जेल, बालोद | 1. श्री दानमल जैन 2. श्री देवलाल चौधरी | मु. पो. बालोद मु. परसदा, पो. सांतरा |
| 7. | उप जेल, बेमेतरा | 1. श्री सनत सिंह ठाकुर 2. श्री हरबंश सिंह | विद्यानगर, बेमेतरा पंजाबी पाग, बेमेतरा |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------------------------|---|---|
| 8. | केन्द्रीय जेल, रायपुर | 1. श्री राजु राघवानी 2. श्री दीपक पंजवानी 3. श्री कैलाश राजपूत 4. श्री राधे दुर्गा 5. श्री नरेश साह 6. श्री विजय देशमुख 7. श्रीमती इंदिरा जैन 8. श्रीमती सुमन तारि पराडकर | तेलीयाधा, रायपुर गंजपाड़ा, नमीचंद गली, रायपुर गोलवाजार, रायपुर मोदहापाड़ा, रायपुर कांया लोधीपाड़ा, रायपुर गोलवाजार, रायपुर चौबे कालोनी, रायपुर बुढ़ापाड़ा, रायपुर |
| 9. | उप जेल, बलीदाबाजार | 1. श्री उमेश वाजपेयी 2. श्री दुर्गा महेश्वर | मु. पो. बलीदाबाजार मु. पो. पत्तारी |
| 10. | उप जेल, गरियाबंद | 1. श्री मुरलीधर सिन्हा 2. श्री भागवत हरित | मु. पो. गरियाबंद मु. पो. फिंगेश्वर |
| 11. | जिला जेल, रायगढ़ | 1. श्री रविन्द्र भाटिया 2. श्री सतीश बेहरा 3. श्री सुरेश गोयल | कोतरा रोड तमनार रायगढ़ |
| 12. | जिला जेल, कोरवा | 1. श्री दीप नारायण सिंह 2. श्री बनारसी दास 3. श्री अनूप अग्रवाल | ग्राम पोस्ट कोरवा नगोडगुआ, दर्गो मु. पो. कोरवा |
| 13. | उप जेल, कटघोरा | 1. मो. हनीफ खान 2. श्री राकेश पांडे | ग्रा. पो. कटघोरा पुरानी बस्ती कटघोरा |
| 14. | जिला जेल, बैकुंठपुर | 1. श्री आशीष गुप्ता 2. श्री विजय राजवाड़े 3. श्री शोएब अहमद | अधिवक्ता, बैकुंठपुर सरडी बैकुंठपुर बैकुंठपुर |
| 15. | उप जेल, मनेन्द्रगढ़ | 1. श्री विवेक अग्रवाल 2. श्रीमती अलका गांधी | बस स्टैंड, मनेन्द्रगढ़ बार्ड नं. 12, मनेन्द्रगढ़ |
| 16. | केन्द्रीय जेल, बिलासपुर | 1. श्री नारायण तावड़ेकर 2. श्री गिरीश शुक्ला 3. श्री अर्जुन तीर्थानी 4. श्रीमती कमला दीक्षित 5. श्री नरेंद्र कछवाहा 6. श्री उदय मोटवानी 7. श्रीमती भीमा पांडेय 8. श्री दीपक खंडेलवाल | राजेंद्र नगर बिलासपुर ग्राम पोस्ट मुंगली सरकगढ़ा बिलासपुर डमलीपाड़ा बिलासपुर मुकाम पोस्ट बिलासपुर मुकाम पोस्ट बिलासपुर पापंद, आजाद नगर बिलासपुर साई मंगलम बिलासपुर |
| 17. | केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर | 1. श्री बलवीर सिंह चावरा 2. श्रीमती विदेश्वरी सिंह | ग्राम पोस्ट अंबिकापुर ग्राम पोस्ट अंबिकापुर |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | 3. श्री काशीनाथ तिवारी | ग्राम पोस्ट अंबिकापुर |
| | | 4. श्री राजकुमार बंसल | ग्राम पोस्ट अंबिकापुर |
| | | 5. श्री कुलदीप सिंह | ग्राम पोस्ट दर्गमा जिला सग्गुजा |
| | | 6. श्रीमती माया मिश्रा | मिशन चौक अंबिकापुर |
| | | 7. श्री रामखिलावन शास्त्री | मुकाम पोस्ट सिलगफली अंबिकापुर |
| | | 8. श्री अशोक सिंह | स्कूल रोड अंबिकापुर |
| 18. | उप जेल, सूरजपुर | 1. श्री अनिल गायल | ग्राम पोस्ट नवापास सूरजपुर |
| | | 2. श्री सतीश गर्ग | ग्राम पोस्ट बकौल कालोनी सूरजपुर |
| 19. | उप जेल, रामानुजगंज | 1. श्री सुभाष जायसवाल | ग्राम पोस्ट रामानुजगंज |
| | | 2. श्री अमीरचंद | ग्राम पोस्ट रामानुजगंज, जि. मरगुजा |
| 20. | उप जेल, जांजगीर-चांपा | 1. श्री बद्रीप्रसाद कटकवार | ग्राम पोस्ट भाटापास जांजगीर |
| | | 2. श्री प्रशांत ठाकुर | मुकाम पोस्ट जांजगीर |
| 21. | जिला जेल, जशपुर | 1. श्री अरूण सिंह | वार्ड नं. 1 जशपुर |
| | | 2. श्री आलोकराय | मुकाम पोस्ट जशपुर नगर |
| | | 3. श्री प्रभाकर यादव | मुकाम पोस्ट कामनतावा जिला जशपुर |
| 22. | उप जेल, कांकेर | 1. श्री सुन्दर हिरदानी | मुकाम पोस्ट कांकेर |
| | | 2. श्री संजय खटवानी | मुकाम पोस्ट कांकेर |
| 23. | केन्द्रीय जेल, जगदलपुर | 1. श्री शशिशंकर शुक्ला | नयापास जगदलपुर |
| | | 2. श्री खीरराज संचेती | प्रतापदेव वार्ड जगदलपुर |
| | | 3. श्री उमाकांत सिंह | राजेंद्र नगर वार्ड जगदलपुर |
| | | 4. श्रीमती पार्वती कश्यप | साकेत कालोनी जगदलपुर |
| | | 5. श्री हेमकांत दास | मुकाम पोस्ट पथगमुड़ा जिला जगदलपुर |
| | | 6. श्री साधूराम निम्बाद | मुकाम पोस्ट कचौरा जिला जगदलपुर |
| | | 7. श्री संतोष त्रिपाठी | विजय वार्ड जगदलपुर |
| | | 8. श्रीमती बसवीर कौर | सदर वार्ड जगदलपुर |
| 24. | उप जेल, दंतेवाड़ा | 1. श्री दुर्गा प्रकाश सिंह चौहान | मुकाम पोस्ट दंतेवाड़ा |
| | | 2. श्री अरूण सिंह भदौरिया | मुकाम पोस्ट गार्दगस |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. धुर्वे, विशेष सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/एफ-1-8/03/(6)52.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :—

- (अ) बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे.
- (ब) बोर्ड के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, संस्कृति विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग शासकीय सदस्य होंगे.
- (स) बोर्ड के संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुए शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.
- (द) बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे.
- (इ) वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ही बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में समायोजित किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

Raipur, the 21st July 2004

No. F-1-8/03/(6) 52.—For the development of handicraft activities in the State, the State Government hereby constitutes the Chhattisgarh Handicrafts Development Board as follows :—

- (A) The Minister in charge of Gramodyog shall be the Chairman of the Board.
- (B) The Principal Secretary/Secretary in charge of Rural Industries, Finance, Culture and Tribal Welfare Departments shall be official members on the Board of Directors.
- (C) Craftsmen/Persons associated with handicrafts and social service sectors may be nominated to the Board as non-official members.
- (D) The Principal Secretary/Secretary of Rural Industries Department, or the Managing Director of the Khadi and Village Industries Board shall be the Managing Director of the Board.
- (E) The staff of Handicrafts cell, shall constitute the staff of the Board.

This notification shall become effective from the date of its notification in the gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेनु जी. पिछे, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2004

क्रमांक आर-216/13/03.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 (ए) तथा (सी) के प्रावधान के अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा। इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन एतद्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालक संचालक, पावर फायनंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, अन्य आदेश तक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कार्यभार से मुक्त होंगे।

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 927/216/13/1/03.—राज्य शासन ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 714/13/650/ऊ. वि./03 दिनांक 24-7-2004 द्वारा श्री बाबू एन. जौहरी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सदस्य (पारंपरण एवं वितरण) के पद पर छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 6 माह जो पहले हो तक वृद्धि देते हुए नियुक्त किया गया है। को संवाहक तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-7/16/2004.—शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्वकर्मा जयंती, 17 सितम्बर को "छत्तीसगढ़ श्रम दिवस" घोषित किया जाए। अतः विश्वकर्मा जयंती दिनांक 17 सितम्बर को "छत्तीसगढ़ श्रम दिवस" घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट हांगडोला, प्रमुख सचिव।

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 10-1/16/2004.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने

के उद्देश्य से राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति का गठन करता है जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(अ) शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति :—

| | | |
|--|---|------------|
| (1) श्री अरूण चौबे, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर | : | अध्यक्ष |
| (2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर | : | सदस्य/सचिव |
| (3) संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर. | : | सदस्य |
| (4) संचालक, नियोजन एवं प्रतिरक्षण संचालनालय, रायपुर. | : | सदस्य |
| (5) संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर | : | सदस्य |

(ब) नियोजकों के प्रतिनिधि :—

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| (1) संचालक, वनोपज निगम, रायपुर | : | सदस्य |
| (2) संचालक, मंडी बोर्ड, रायपुर | : | सदस्य |
| (3) नियोजक, गोला बीड़ी, धमतरी | : | सदस्य |

(स) श्रमिक प्रतिनिधि :—

| | | |
|---|---|-------|
| (1) श्री सत्येंद्र दुबे, छत्रपति शिवाजी नगर, एच. आई. जी. 82, हुडको कालोनी, जिला कोरबा. | : | सदस्य |
| (2) श्रीमती लता दीक्षित, मु. पो. कोगियाकला, तहसील साजा, जिला दुर्ग. | : | सदस्य |
| (3) श्रीमती बेबी जोस, सरकारी कुएं के पास, वार्ड नं.-2 कोटा, पो. आ. रविशंकर युनिवर्सिटी, रायपुर. | : | सदस्य |

(द) स्वतंत्र सदस्य :—

| | | |
|---|---|-------|
| (1) श्रीमती नीलम बाला सालोमन, अध्यक्ष महिला इंटक | : | सदस्य |
| (2) श्रीमती उमा नेताम द्वारा बी. एल. नेताम, 38/ए, बालको नगर कोरबा. | : | सदस्य |
| (3) सुश्री राजकुमारी राज तुलाली पो. लाफा, व्हाया-पाली जिला कोरबा. | : | सदस्य |
| (4) श्रीमती गुलाब बाई परमान, समता कालोनी, रायपुर | : | सदस्य |
| (5) श्रीमती प्रभा पटेल, मु. पो.-देवकर, जिला दुर्ग. (श्री रंजन जी पटेल). | : | सदस्य |
| (6) श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम, कृषि उपज मंडी के सामने, जगदलपुर. | : | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पारसनाथ राम, अवग सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2004

संशोधन

क्रमांक/1567/बी-11/8/2003-04/14-2.—विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6162-6163/बी-11/8/2003 04/14-2. दिनांक 6-2-2004 में संलग्न सूची के क्रमांक-2 गेहूं असिंचित जिला राजनांदगांव के सम्मुख दर्शित बिन्दु क्रमांक-2 तहसील डोंगरगांव को खिलोपित करते हुए डोंगरगढ़ स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

सी. एल. जैन, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

संशोधन

फा. क्रमांक 5245/3 (बी)/28/2004/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5210/3 (बी)/28/2004/21-ब दिनांक 27-8-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश की प्रतिलिपि क्रमांक 1 की पंक्ति 4 में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री बिहारी राम के स्थान पर श्रीमती मृनाता टोप्पो, पत्नी श्री निर्मल टोप्पो पढ़ा जावे.

रायपुर दिनांक 28 अगस्त 2004

संशोधन

फा. क्रमांक 5246/3 (बी)/29/2004/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5208/3 (बी)/29/2004/21-ब दिनांक 27-8-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश की प्रतिलिपि क्रमांक 1 की पंक्ति 4 में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री बिहारी राम के स्थान पर श्री गुरुप्राप्त सिंह मरकाम पिता श्री निर्मल सिंह मरकाम पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5747/डी-2286/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के जापन क्रमांक 348/बी-2-17/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री दिलीप कुमार भट्ट, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, दुर्ग को सेवायें छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सूची जाती है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5748/डी-2291/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 340/डी-2 10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्रीमती अनिता झा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर की सेवाएँ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूची जाती है।

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5749/डी-2288/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 341/डी-2 10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर को सेवाएँ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल से वापस लेते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में अतिरिक्त सचिव के पद पर एतद्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5750/डी-2292/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 345/डी-2 16/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री अरुण कुमार प्रधान, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कांकेर, छ. ग. को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एतद्वारा सूची जाती है।

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5752/डी-2287/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 347/डी-2 10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्रीमती विमला सिंह कपूर, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में उप सचिव के पद पर एतद्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2004

संशोधित आदेश

फा. क्र. 5765/डी/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5750/डी-2292/21 ब/छ.ग./04 दिनांक 21 9 04 की पांचवी पंक्ति में "दुर्ग" के स्थान पर राजनांदगांव पढ़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. सी. ब्राजपेयी, प्रमुख सचिव,

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5751/डी-2290/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 346/डी-2 10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री टी. पी. शर्मा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) की सेवाएँ विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को सूची जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. निकुन्ज, अतिरिक्त सचिव,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 13 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | मोहदा | 1.955 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रा रोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 14 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | डोंगी | 0.627 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रा रोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 15 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | नवागांव | 0.834 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 16 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | तिलकडीह | 0.238 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 17 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | बिरगहनी | 2.444 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 18 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | पोड़ी | 0.777 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 19 अ 82/2003-04. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | सेमरा | 0.101 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड. | चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्र. 34 /अ-82/2003-04. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | मस्तुरी | खम्हरिया | 0.312 | कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग क्रमांक 1, बिलासपुर | खम्हरिया विटकुला मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्र. 35 /अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, उसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|--------|---------------|---------------------------|---|--|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | बिल्हा | बोदरी | 3.78 | छ. ग. शासन, राजस्व विभाग | उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर के न्यायालयीन भवन निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 सितम्बर 2004

क्रमांक 357/अ.वि.अ./भू-अर्जन/26 अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, उसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-----------|-----------|--|-------------------------------|---|---|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | महासमुन्द | मोंगरपाली/तेन्दूकोना प. ह. नं. 121/68 | 0.57 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, रायपुर. | मच्छा नाला पिथौरा, राग बाहर मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 6846/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | पटपर प. ह. नं. 31 | 9.44 | कार्यालयन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, | भर सार्वजनिक उपयोग के लिये नदी निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्र. 79/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10644. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|-------|----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | रजगामार प. ह. नं. 10 | 0.25 | मुख्य महाप्रबंधक, एस. ई. पी. एन. कोरबा पूर्व, | पवन सफाई के लिये नदी भूमि का अर्जन |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/03-04/15/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें शासन अनुरोध के खाने (1) में (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके मामले दिये गये मावजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्दिष्ट अधिकारों को एक भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | मावजानिक प्रयोजन |
|-------|---------|---------------|------|--|--------------------------------|------------------|
| | | नगर/ग्राम | | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| बस्तर | जगदलपुर | बड़े आमावाल | 0.60 | वन मण्डलाधिकारी (सा) वन मण्डल, जगदलपुर, | | वांग रोपण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्रमांक 6192/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें शासन अनुरोध के खाने (1) में (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके मामले दिये गये मावजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्दिष्ट अधिकारों को एक भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसको गव में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | मावजानिक प्रयोजन |
|----------------------------|------------|---------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | नगर/ग्राम | | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | कारली | 0.81 | मेनानी, 9वीं बटा, छ. म. मशख पुलिस, जिला दन्तेवाड़ा, | | मावजानिक प्रयोजन हेतु |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. पिस्टा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2004

रा. प्र. क्र. 01 अ 82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|-----------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | नगर/ग्राम | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| सरगुजा | प्रतापपुर | प्रतापपुर | 0.55 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) | पहुँच मार्ग के लिए |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/216.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन को यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसको गवर्नर के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भाग 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | नगर/ग्राम | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | हरेठीकला प.ह.नं. 22 | 0.348 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाला बांगो नहर संभाग, क्र. 3, यक्ता. | संरक्षकता बांगो नहर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

निधि छिव्यर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/311.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्वये इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गथ में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| | | भूमि का वर्णन | धारा 4 की उपधारा (2) | | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सकरा प.ह.नं. 07 | 0.101 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता चांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा | कटांगे चांग माइन्ड 4 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/312.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्वये इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गथ में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| | | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अडभार प.ह.नं. 8 | 0.132 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता चांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोदोह चांग माइन्ड नं. 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/313.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसमें द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित आवश्यकता को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गत में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नौरंगपुर प.ह.नं. 07 | 0.248 | कार्यपालन यंत्रो, मिर्नामाता चांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभग. | भागोदीह माइटर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/405.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसमें द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित आवश्यकता को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गत में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | देवरघटा प.ह.नं. 22 | 0.114 | कार्यपालन यंत्रो, मिर्नामाता चांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | देवरघटा माइटर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/406.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | लगाभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | नगर/ग्राम | | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | तुपीडीह प.ह.नं. 22 | | 0.354 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती | गृह मंडल |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना-सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/407.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | लगाभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | नगर/ग्राम | | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | परसाडीह प.ह.नं. 16 | | 1.345 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती | घोराडीपा मांडल |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/408.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, उस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गत में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | बरेकेल खुर्द प.ह.नं. 21 | 0.368 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सकी. | बरेकेल बांध माडन I R |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सकी/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/409.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, उस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गत में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | गलगलाडीह प.ह.नं. 13 | 0.324 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सकी. | गलगलाडीह माडन |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सकी/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/410.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|-----------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सकरा | 0.132 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कटारी माइन |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/411.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आमनडुला प.ह.नं. 3 | 0.057 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | करिगांव माइनर 3 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/412.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | चंदेलाडीह प. ह. नं. 2 | 0.750 | कार्यपालन यंत्रो, मिनीमाता चांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कारिगांव माइभर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/413.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मोहतरा प.ह.नं. 3 | 1.284 | कार्यपालन यंत्रो, मिनीमाता चांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | पोता उप विवरण सामुदायिक माइभर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/414.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | चंदेलाडीह प.ह.नं. 2 | 0.137 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कारिगांव सव माइनर 3 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/416.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अडभार प.ह.नं. 8 | 0.389 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अडभार माइनर 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7148/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | मोंगरा प.ह.नं. 21 | 13.770 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के वायों तट मुख्य नहर निर्माण के लिये. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7149/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | झिटिया प.ह.नं. 3 | 5.359 | कार्यपालन अभियंता, - मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा क्षेत्र में मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दृष्टान क्षेत्र |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7150/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अ. चौकी | मुंजाल प.ह.नं. 20 | 2.293 | कार्यपालन अभियंता, - मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दृष्टान क्षेत्र. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7151/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | दानीटोला प.ह.नं. 21 | 12.053 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दृष्टान क्षेत्र |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7152/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में एक धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | कुमरदा प.ह.नं. 61 | 15.012 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अंतर्गत वायों तट नहर के डोंगरगांव वितरण, जाग्रदा नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7153/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में एक धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | अछोली प.ह.नं. 60 | 7.650 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अंतर्गत वायों तट नहर के डोंगरगांव वितरण, जाग्रदा नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7154/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संयोजित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | आमगांव प.ह.नं. 60 | 6.290 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अंतर्गत ब्याची नद नहर के डोंगरगांव वितरण शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7155/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संयोजित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | सोमाझिटिया प.ह.नं. 59 | 2.982 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अंतर्गत ब्याची नद नहर के डोंगरगांव वितरण शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7156/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | खुर्सीटिकुल प.ह.नं. 64 | 1.862 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7157/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | कान्हे प.ह.नं. 12 | 0.765 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास/कान्हा के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

अनुसूची

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7144/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 67/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| 127/1 | 0.76 |
| 127/3 | 0.15 |
| 127/2 | 0.15 |
| योग | 3 |
| | 1.06 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7145/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-यसंतपुर, प. ह. नं. 66
(घ) लगभग क्षेत्रफल 73.06 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| 2 | 1.70 |
| 117 | 1.46 |
| 18 | 1.90 |
| 28 | 5.25 |
| 53/3 | 0.56 |
| 53/5 | 0.48 |
| 57/1 | 1.23 |
| 124 | 1.30 |
| 58 | 0.84 |
| 62 | 1.00 |
| 65/1 | 0.48 |
| 66/3 | 0.40 |
| 140/1 | 0.40 |
| 116 | 1.72 |
| 139/6 | 0.13 |
| 115 | 1.52 |
| 129 | 0.32 |
| 10/2 | 0.05 |
| 51/2 | 0.10 |
| 139/2 | 0.14 |
| 5 | 0.07 |
| 8 | 0.38 |
| 19 | 0.10 |
| 29 | 1.25 |
| 67/1 | 0.10 |
| 54 | 1.30 |
| 60 | 2.20 |
| 125 | 0.92 |
| 59 | 1.00 |
| 64/1 | 1.45 |
| 65/3 | 0.33 |
| 66/2 | 0.27 |

| (1) | (2) |
|-------|-------|
| 140/2 | 1.11 |
| 139/1 | 0.13 |
| 137 | 0.42 |
| 119 | 1.14 |
| 130 | 0.03 |
| 14/1 | 0.50 |
| 135/1 | 0.92 |
| 6/3 | 0.20 |
| 15 | 0.65 |
| 63 | 0.50 |
| 53/1 | 1.40 |
| 67/3 | 0.10 |
| 55 | 1.36 |
| 114 | 1.75 |
| 57/2 | 0.35 |
| 126 | 0.58 |
| 138 | 1.98 |
| 65/2 | 0.43 |
| 118 | 1.79 |
| 140/3 | 0.45 |
| 139/4 | 0.20 |
| 136 | 0.90 |
| 121 | 2.63 |
| 131 | 1.12 |
| 13/1 | 0.25 |
| 145/2 | 0.70 |
| 7 | 0.52 |
| 17 | 0.36 |
| 139/5 | 0.15 |
| 53/2 | 0.73 |
| 53/4 | 0.46 |
| 56 | 0.90 |
| 120/1 | 0.84 |
| 120/2 | 0.27 |
| 61 | 13.06 |
| 64/2 | 0.75 |
| 66/1 | 0.13 |
| 67/2 | 0.11 |
| 127 | 0.32 |
| 139/3 | 0.15 |
| 113 | 0.98 |
| 128 | 0.62 |
| 364/2 | 0.35 |

| (1) | (2) |
|--------|-------|
| 13/2 | 0.27 |
| 145/3 | 0.15 |
| योग 77 | 73.06 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है खेतीयता चलायय योजना के बांधपार एवं इयान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्गक्षण भू-अर्जन अधिनियम, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7146/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.63 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| 720 | 3.96 |
| 723 | 0.60 |
| 721 | 0.45 |
| 722 | 0.15 |
| 724/1 | 0.28 |
| 724/2 | 0.33 |
| 724/3 | 0.33 |
| 724/7 | 0.05 |
| 724/4 | 0.23 |
| 724/5, 6 | 0.60 |
| 740 | 0.18 |

| (1) | (2) |
|-----|---------|
| 738 | 0.05 |
| 745 | 0.08 |
| 746 | 0.34 |
| योग | 14 7.63 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 शीर्ष कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7147/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.04 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| 591 | 0.09 |
| 592 | 0.02 |
| 594 | 0.07 |
| 588 | 0.15 |
| 601/2 | 0.20 |
| 651 | 0.13 |
| 601/1 | 0.16 |
| 599 | 0.04 |
| 598 | 0.07 |
| 618/3 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|-------|---------|
| 618/1 | 0.03 |
| 619 | 0.07 |
| 620 | 0.05 |
| 629/3 | 0.03 |
| 630 | 0.22 |
| 631 | 0.04 |
| 632 | 0.05 |
| 633 | 0.05 |
| 627 | 0.20 |
| 626/4 | 0.08 |
| 626/3 | 0.15 |
| 626/2 | 0.07 |
| 625/3 | 0.04 |
| 644 | 0.11 |
| 641 | 0.07 |
| 662/2 | 0.06 |
| 653/2 | 0.26 |
| 653/1 | 0.52 |
| 652 | 0.08 |
| 640 | 0.07 |
| 639 | 0.06 |
| 638 | 0.04 |
| 663 | 0.51 |
| 651/1 | 0.06 |
| 662/1 | 0.57 |
| 650/2 | 0.60 |
| 649 | 0.18 |
| 648/2 | 0.22 |
| 648/1 | 0.57 |
| योग | 39 6.04 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 शीर्ष कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 6852/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-चौकी

(ग) नगर/ग्राम-दुर्रौटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.840 हेक्टेयर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक भू-अर्जन/48-अ/82/2002 2003. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गंडापाली, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 21.537 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 2 | 0.725 |
| 3 | 0.405 |
| 6/2 | 2.436 |
| 19/1 | 1.121 |
| 21/3 | 0.407 |
| 19/2 | 0.347 |
| 27/4 | 0.736 |
| 21/4 | 0.350 |
| 27/5 | 0.445 |
| 27/1 | 0.198 |
| 21/1 | 0.632 |
| 20/1 | 0.404 |
| 27/3 | 0.534 |
| 20/3 | 0.166 |
| 21/5 | 0.720 |
| 20/2 | 0.324 |
| 21/2 | 0.445 |
| 27/2 | 0.445 |

योग 18 10.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मंगरा परियोजना के बांध एवं ड्रियन क्षेत्र के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 3/18 | 0.809 |
| 3/29 | 2.975 |
| 2/1 | 0.975 |
| 2/2 | 0.190 |
| 3/23 | 0.429 |
| 3/24 | 0.445 |
| 3/2 | 0.672 |
| 3/25 | 0.745 |
| 3/28 | 0.405 |
| 3/3 | 0.486 |
| 3/4 | 0.101 |
| 3/5 | 0.089 |
| 3/36 | 0.105 |
| 3/37 | 0.105 |
| 3/38 | 0.040 |
| 4 | 0.688 |
| 3/20 | 0.707 |
| 3/6 | 0.648 |
| 3/7 | 0.685 |

| (1) | (2) | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|--------|---------------|------------------------|
| | | (1) | (2) |
| 6 | 0.214 | | |
| 7 | 0.348 | | |
| 3/9 | 1.003 | | |
| 9/2 | 0.486 | 2 | 0.693 |
| 3/11 | 0.904 | 383/13 | 1.012 |
| 9/1 | 1.287 | 383/18 | 0.607 |
| 3/10 | 1.052 | 383/19 | 0.809 |
| 3/16 | 0.069 | 383/12 | 1.125 |
| 3/60 | 1.526 | 383/14 | 0.983 |
| 3/15, 3/35 | 0.613 | 383/16 | 0.304 |
| 3/34 | 0.081 | 383/2 | 1.214 |
| 3/19 | 0.175 | 383/17 | 0.607 |
| 3/44 | 0.079 | 383/3 | 1.214 |
| 3/45 | 0.093 | 383/4 | 1.214 |
| 3/46 | 0.126 | 383/15 | 0.809 |
| 17 | 0.571 | 383/5 | 1.214 |
| 3/22 | 0.073 | 383/6 | 1.214 |
| 3/21 | 0.142 | 7/1 ख | 0.672 |
| 3/8 | 0.607 | 7/1 ग | 0.053 |
| 3/49 | 0.809 | 7/2 | 0.263 |
| योग 39 | 21.537 | 8/1 | 1.189 |
| | | 8/2 | 0.837 |
| | | 8/3 | 0.081 |
| | | 8/4 | 0.097 |
| | | 8/5 | 0.081 |
| | | 8/6 | 0.097 |
| | | 8/10 | 0.097 |
| | | 8/11 | 0.081 |
| | | 8/9 | 0.162 |
| | | 9/1 | 0.607 |
| | | 7/1 घ | 0.097 |
| | | 383/8 | 0.607 |
| | | 383/7 | 0.202 |
| | | 17/3 एवं 18 3 | 0.534 |
| | | 17/2 एवं 18 2 | 0.202 |
| | | 20 | 0.101 |
| | | 17/1 एवं 18 1 | 0.515 |
| | | 1/2 क | 0.101 |
| | | 1/2 ख | 0.101 |
| | | 21/1 | 0.101 |
| | | 21/2 | 0.073 |
| | | 3 | 0.101 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरदिया जलाशय के इन्धन क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाई-गढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक भू अर्जन/49-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन.

(क) जिला रायपुर

(ख) तहसील बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम दर्जा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 32.132 हेक्टेयर

| (1) | (2) | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------|-------|------------|------------------------|
| | | (1) | (2) |
| 4 | 0.696 | 129/1 च | 0.109 |
| 5 | 0.364 | 131/3 | 0.126 |
| 383/1 | 5.583 | 130/1 | 0.016 |
| 7/1 क | 3.100 | 131/1 ख | 0.060 |
| 19 | 0.025 | 132/1 | 0.048 |
| 1/1 | 1.955 | 134/8 | 0.024 |
| 8/7 | 0.081 | 243/3 | 0.065 |
| 8/8 | 0.093 | 143/2 | 0.040 |
| योग | 47 | | 32.132 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरदिया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाई-गढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 355/सां-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-भातमाहुल, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.488 हेक्टेयर

योग 0.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भातमाहुल माडनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राज्य प्रयोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 415/सां-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मानखुरगैदा
(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| पोता उप वितरक | |
| 70/1 | 0.040 |
| 168/1 | 0.020 |
| 168/3 | 0.073 |

| (1) | (2) | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पाता उप वित्तम्भ, सारसडोल माइनर. |
|---------------|-------|---|
| 168/4 | 0.004 | |
| 75/1 | 0.073 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हमदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| 19/2 | 0.065 | |
| 23/1 | 0.065 | |
| सारसडोल माइनर | | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, |
| 629 | 0.143 | बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप मन्त्रि. |
| योग | 0.483 | |

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 24 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 24 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभागी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | उसलापुर/35 | 154/7 | 0.54 |
| | | | 139 | 0.31 |
| | | | 142 | 0.22 |
| | | | 135/2 | 0.20 |
| | | | 140 | 0.35 |
| | | | 196/2 | 0.10 |
| | | | 141/2 | 0.24 |
| | | | 195/2 | 0.70 |
| | | | 195/5 | 0.25 |
| | | | 135/1 | 0.01 |
| | | | 195/6 | 0.20 |
| | | | 196/3 | 0.26 |
| | | | 154/6 | 0.20 |
| | | | 196/6 | 0.10 |
| | | कुल | 14 | 3.68 |

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 25 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 31अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सोपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विहंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | दवनडीह/36 | 90/13 | 0.35 |
| | | | 90/14 | 0.25 |
| | | | 58/1 | 0.10 |
| | | | 78/5 | 0.30 |
| | | | 78/4 | 0.25 |
| | | | 40/1 | 0.05 |
| | | | 132/2 | 1.06 |
| | | | 76/5 | 0.30 |
| | | | 96 | 0.28 |
| | | | 40/3 | 0.16 |
| | | | 76/3 | 0.35 |
| | | | 49 | 0.40 |
| | | | 48/3 | 0.35 |
| | | | 61/2 | 0.40 |
| | | | 76/1 | 0.15 |
| | | | 56/1 | 0.60 |
| | | | 56/6 | 0.15 |
| | | | 57/1 | 0.20 |
| | | | 75/2 | 0.18 |
| | | | 76/2 | 0.03 |
| | | | 61/1 | 0.18 |
| | | | 48/2 | 0.07 |
| | | | 132/4 | 0.42 |
| | | | 76/4 | 0.24 |
| | | | 75/1 | 0.27 |
| | | | 90/6 | 0.33 |
| | | | 62/1, 62/2, 62/3 | 0.50 |
| | | | 97 | 0.67 |
| | | | 39/1 | 0.49 |
| | | | 39/5 | 0.15 |
| | | | 39/2 | 0.30 |
| | | | 39/3 | 0.08 |
| | | | 56/3, 56/5 | 0.46 |
| | | | 59 | 0.54 |
| | | | 48/1 | 0.86 |
| | | | 60 | 0.60 |
| | | | 39/4 | 0.18 |
| | | | 56/4 | 0.36 |
| | | | 40/7 | 0.18 |
| | | | 58/3 | 0.12 |
| कुल | | | 40 | 12.91 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 26 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 26 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर उसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभागी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विवर्गों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जन की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | करा/36 | 264, 267 | 0.08 |
| | | | 245/3 | 0.31 |
| | | | 254/2, 255/2 | 0.07 |
| | | | 245/1 | 0.55 |
| | | | 254/1 | 0.20 |
| | | | 270/2 | 0.03 |
| | | | 235/1 | 0.03 |
| | | | 272/1 | 0.20 |
| | | | 253 | 0.12 |
| | | | 235/3 | 0.25 |
| | | | 268 | 0.95 |
| | | | 231 | 0.74 |
| | | | 269/2 | 0.78 |
| | | | 233/2 | 0.05 |
| | | | 235/7 | 0.50 |
| | | | 232/1 | 0.58 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|--------------|------|
| | | | 233/1 | 0.88 |
| | | | 235/2 | 0.32 |
| | | | 235/4 | 0.03 |
| | | | 243/1 | 0.80 |
| | | | 245/2, 245/5 | 0.25 |
| | | | 269/1 | 0.60 |
| | | | 245/4 | 0.45 |
| | | | 272/2 | 0.03 |
| | | | 243/3 | 0.07 |
| | | | 266 | 0.80 |
| | | कुल | 26 | 9.47 |

विलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 27 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), विलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 27 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-विलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा एतत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | धनियाँ/35 | 292/4 | 0.70 |
| | | | 292/3, 297/1 | 0.40 |
| | | | 292/9, 297/3 | 0.01 |
| | | | 296/5 | 0.02 |
| | | | 292/2, 292/13 | 0.24 |
| | | | 292/11, 297/4 | 0.20 |
| | | | 296/4 | 0.05 |
| | | कुल | 11 | 1.62 |

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 28 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 28 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परियोजना के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आदेश को घोषणा की थी,

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आदेश को घोषणा की थी,

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है,

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हेतु यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है,

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विध्वंसकों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा,

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | कुरुली/34 | 756 | 0.20 |
| | | | 244/1 | 0.20 |
| | | | 244/2 | 0.58 |
| | | | 244/3 | 0.60 |
| | | | 96 | 0.80 |
| | | | 154/2 | 0.18 |
| | | | 169/5 | 0.32 |
| | | | 549 | 1.32 |
| | | | 750 | 0.24 |
| | | | 704 | 0.21 |
| | | | 237 | 0.20 |
| | | | 167/2 | 0.03 |
| | | | 152 | 0.54 |
| | | | 703 | 0.12 |
| | | | 755 | 0.34 |
| | | | 758 | 0.23 |
| | | | 757 | 0.06 |
| | | | 167/1 | 0.36 |
| | | | 746 | 0.22 |
| | | | 747, 748 | 1.43 |
| | | | 98 | 0.54 |
| | | | 535 | 1.13 |
| | | | 705 | 0.10 |
| | | | 738 | 0.30 |
| | | | 538 | 0.27 |
| | | | 97 | 0.30 |
| | | | 153 | 0.32 |
| | | | 241 2 | 0.10 |
| | | | 169 2 | 0.26 |
| | | | 154 1 | 0.22 |
| | | | 736 2 | 1.30 |
| | | | 737 | 0.20 |
| | | | 554 | 0.30 |
| | | | 169 4 | 0.38 |
| | | | 70 | 0.15 |
| | | | 751 | 0.30 |
| | | | 167 3 | 0.32 |
| | | | 221 | 0.32 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|-------|-------|
| | | | 261/1 | 1.04 |
| | | | 548 | 0.26 |
| | | | 552 | 0.10 |
| | | | 553 | 0.09 |
| | | | 163 | 0.13 |
| | | | 169/1 | 0.02 |
| | | | 242/1 | 0.28 |
| | | | 240 | 0.04 |
| | | | 148/2 | 0.18 |
| | | | 166/1 | 0.30 |
| | | | 752 | 0.13 |
| | | | 550 | 0.24 |
| | | | 260 | 0.01 |
| | | कुल | 53 | 18.62 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 29 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 29 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, नहरमालदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिधामी/अधिपति को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विहंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | खम्हरिया/34 | 320/3 | 0.26 |
| | | | 313/1 | 0.32 |
| | | | 334 | 0.36 |
| | | | 598, 599 | 0.86 |
| | | | 589/1 | 0.14 |
| | | | 406 | 0.22 |
| | | | 408 | 1.29 |
| | | | 616/1 | 0.40 |
| | | | 315/1 | 0.16 |
| | | | 320/2 | 0.18 |
| | | | 437 | 0.30 |
| | | | 439 | 0.08 |
| | | | 309/1 | 0.42 |
| | | | 394 | 0.08 |
| | | | 296/5 | 0.40 |
| | | | 297/2 | 0.32 |
| | | | 611/6 | 0.80 |
| | | | 607/1 | 0.08 |
| | | | 323 | 1.22 |
| | | | 390 | 0.34 |
| | | | 308 | 0.08 |
| | | | 311 | 0.66 |
| | | | 322 | 0.84 |
| | | | 324 | 0.34 |
| | | | 326 | 0.04 |
| | | | 391 | 0.02 |
| | | | 392 | 0.18 |
| | | | 393 | 0.07 |
| | | | 395 | 0.02 |
| | | | 400 | 0.03 |
| | | | 402 | 0.40 |
| | | | 404 | 0.36 |
| | | | 405/7 | 0.09 |
| | | | 407 | 1.43 |
| | | | 433 | 1.03 |
| | | | 434/1 | 1.04 |
| | | | 438 | 0.12 |
| | | | 312 | 0.11 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|---------------------|-------|
| | | | 333/1 | 0.18 |
| | | | 333/2 | 0.18 |
| | | | 320/4 | 0.29 |
| | | | 309/4 | 0.20 |
| | | | 304/3, 306, 574/2 | 0.76 |
| | | | 309/2, 309/3, 310/2 | 0.53 |
| | | | 296/1 | 0.59 |
| | | | 297/1 | 0.43 |
| | | | 610/1 | 0.18 |
| | | | 611/7 | 0.92 |
| | | | 310/1 | 0.24 |
| | | | 296/6 | 0.85 |
| | | | 298 | 0.06 |
| | | | 320/1 | 0.45 |
| | | | 325 | 0.04 |
| | | | 396 | 0.19 |
| | | | 397 | 0.02 |
| | | | 435 | 0.04 |
| | | | 589/3 | 0.20 |
| | | | 590/1 | 0.05 |
| | | | 405/1 | 0.25 |
| | | कुल | 60 | 21.74 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम '6' देखें)

क्रमांक 30 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 का उपभाग (1) के अर्शन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 30 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामियों/अधिभागों को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आशयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन विद्युतों के लिये भूमि के उपयोग के आधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन विद्युतों के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | परसाही/36 | 147/4 | 0.10 |
| | | | 148 | 0.53 |
| | | | 140/2 | 0.35 |
| | | | 145/1 | 0.10 |
| | | | 142 | 0.30 |
| | | | 157 | 0.50 |
| | | | 147/3 | 0.30 |
| | | | 139 | 0.16 |
| | | | 151 | 0.35 |
| | | | 147/6 | 0.84 |
| | | | 149/1 | 1.00 |
| | | | 138/2 | 0.40 |
| | | | 158/1 | 0.54 |
| | | | 143/2 | 0.10 |
| | | | 144 | 0.10 |
| | | | 140/1 | 0.40 |
| | | | 141/2 | 0.10 |
| | | | 149/2 | 0.60 |
| | | | 143/1 | 0.60 |
| | | | 112/3 | 0.15 |
| | | | 150 | 0.18 |
| | | | 156 | 0.15 |
| | | | 166/2, 167 | 0.07 |
| कुल | | | 23 | 7.92 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 31 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 31 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सौपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये प्राप्ति पर्यवेक्षण के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आदेश की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आशयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | लुतरा/34 | 745/3 | 0.20 |
| | | | 740/1 | 0.02 |
| | | | 744 | 0.20 |
| | | | 731/1 | 0.02 |
| | | | 741/2 | 0.90 |
| | | | 731/3 | 0.25 |
| | | | 727/2 | 0.42 |
| | | | 737/3 | 0.20 |
| | | | 727/1 | 0.20 |
| | | | 727/3 | 0.15 |
| | | | 656 | 0.18 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|-----------------|------|
| | | | 732/1 | 0.74 |
| | | | 729, 730, 732/3 | 0.05 |
| | | | 738 | 0.03 |
| | | | 739/1 | 0.40 |
| | | | 741/3 | 0.07 |
| | | | 743/4 | 0.07 |
| | | | 742/2, 743/5 | 0.08 |
| | | | 742/4, 743/3 | 0.06 |
| | | | 743/2 | 0.02 |
| | | | 654/2 | 0.52 |
| | | | 737/2 | 0.02 |
| | | | 745/1, 745/2 | 0.25 |
| | | | 736 | 0.10 |
| | | | 657 | 0.32 |
| | | | 654/1, 654/3 | 0.25 |
| | | | 743/1 | 0.12 |
| | | | 737/1 | 0.50 |
| | | | 739/1 | 0.36 |
| | | | 731/2 | 0.28 |
| | | | 743/6 | 0.06 |
| | | कुल | 32 | 7.04 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 32 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अन्विभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 32 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये मार्ग परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभागों को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आशयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाउपलाइन्ड बिल्डिंग के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाउपलाइन्ड बिल्डिंग के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलग्नियों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. नं. | खसरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जन की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|--------------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | भौराडोह/34 | 80/1 | 0.68 |
| | | | 88 | 0.80 |
| | | | 6/1 | 0.02 |
| | | | 3/4 | 0.33 |
| | | | 2 | 0.09 |
| | | | 77/1 | 0.11 |
| | | | 6/6 | 0.36 |
| | | | 75 | 0.06 |
| | | | 80/2 | 0.05 |
| | | | 4 | 0.28 |
| | | | 13 | 0.20 |
| | | | 14 | 0.28 |
| | | | 77/2 | 0.10 |
| | | | 6/5 | 0.28 |
| | | | 6/3 | 0.60 |
| | | | 3 10, 3/11 | 0.40 |
| | | | 3/12, 3/13 | 0.38 |
| | | | 3/9 | 0.56 |
| | | | 81 | 0.28 |
| | | | 71/2 | 0.05 |
| | | | 76/2 | 0.25 |
| | | | 5 | 0.17 |
| | | | 89/4 | 0.20 |
| | | | 74 | 0.50 |
| | | | 76/1 | 0.26 |
| कुल | | | 27 | 7.26 |

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

“प्रारूप-घ”

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 33 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अंजन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 33 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अंजन करने के लिये अपने आदेश की घोषणा की थी,

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामि अधिकारियों को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है,

और, उक्त भूमिगत पाइपलाइन विछाने के संबंध में जनता में प्राप्त आशयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है,

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन विछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अंजन किया जाता है,

और, एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन विछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विध्वंसकों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा,

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खम्बरा नम्बर | उपयोग के अधिकार के लिये अंजन से जारी जाती-भूमि (एकड़ में) |
|----------|---------|-----------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | खाड़ा/35 | 287/5 | 0.12 |
| | | | 289/5 | |
| | | | 315/2 | 0.07 |
| | | | 315/3 | |
| | | | 287/11 | 0.32 |
| | | | 355/1 | 0.02 |
| | | | 355/2 | 0.32 |
| | | | 287/1 | 0.15 |
| | | | 283/1 | 0.15 |
| | | | 283/2 | 0.02 |
| | | | 283/3 | 0.17 |
| | | | 311/2 | 0.02 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|--------------|------|
| | | | 310/2 | 0.38 |
| | | | 346/4 | 0.10 |
| | | | 345/1 | 0.25 |
| | | | 346/3 | 0.24 |
| | | | 310/4 | 0.25 |
| | | | 346/7 | 0.01 |
| | | | 281 | 0.31 |
| | | | 310/1 | 0.25 |
| | | | 286/3 | 0.02 |
| | | | 339/1 | 0.13 |
| | | | 282 | 0.05 |
| | | | 345/2 | 0.32 |
| | | | 346/1 | 0.01 |
| | | | 308/1 | 0.10 |
| | | | 354/1 | 0.48 |
| | | | 357 | 0.33 |
| | | | 346/2 | 0.40 |
| | | | 310/3 | 0.25 |
| | | | 355/1 | 0.02 |
| | | | 286/2 | 0.12 |
| | | | 286/5 | 0.01 |
| | | | 311/1 | 0.16 |
| | | | 287/9, 289/4 | 0.70 |
| | | | 287/2 | 0.08 |
| | | | 317 | 2.12 |
| | | કુલ | 39 | 9.05 |

દસ્તાવેજ

અનુબિભાગીય અધિકારી

અને મુ. અગ્રણ અધિકારી.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2827/4585/क/ख. लि./खु. घो./न. क्र. 51/2000.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के तहत महासमुंद जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र क्वार्टर्जाइंट खनिज के खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये उपलब्ध रहेगा।

| स. क्र. | ग्राम का नाम | प. ह. नं. | खनिज | तहसील | खसरा नंबर | रकबा | अन्य विवरण |
|---------|--------------|-----------|----------------|----------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | परसापाली | 06 | क्वार्टर्जाइंट | सराईपाली | 51/1 टु. 51/2 टु. 51/3 टु. ख. नं. (कुल) 3 | 1.017 हेक्टर 0.065 हेक्टर 0.049 हेक्टर कुल रकबा 1.131 हेक्टर | स्वीकृत अर्वाध समप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है। |

मनिन्दर कौर द्विवेदी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 3771/मा. चि./2003.—म. प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित मांगों में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली चूने के विनिर्माण के लिए भट्टों में डालकर, उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर, उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा।

| क्र. | पूर्व पट्टेदारों का नाम | ग्राम का नाम | तहसील | खसरा नं. | रकबा (एकड़ में) | खनिज का नाम | भूमि का विवरण | खुला घोषित किये जाने का कारण |
|------|-------------------------|--------------|-------|----------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------------|----------------------------|
| 1. | जगदीश प्रसाद अग्रवाल साकिन-दुर्ग. | जोरातराई | राजनांदगांव | 164 एकड़ | 3.99 | चूना पत्थर | शासकीय भूमि | अर्वाध समप्त होने के कारण. |
|----|-----------------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------------|----------------------------|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|---|----------|-------------|--------|---------|------------|--------------|-------------------------------|
| 2. | श्रीमती रंजनबाला ध. प. बृजमोहन साकिन-दुर्ग. | जोरातराई | राजनांदगांव | 320/14 | 2.40 ए. | चूना पत्थर | भूमि ग्रामों | अर्थात् समस्त होम के कागज. |
| | | | | 320/15 | 2.50 ए. | | | |
| | | | | | 4.90 | एकड़ | | |

जी. एम. मिश्रा.

कलेक्टर.